



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2003/ज्येष्ठ 12, 1925

No. 503]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2003/JYAISTHA 12, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2003

का.आ. 644(अ).—चूँकि तम्बाकू बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह सूचित किया गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य में अनेक उपजकर्ताओं द्वारा फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू (जिसे आगे एफसीवी तम्बाकू कहा गया है) की खेती की गयी है जिससे मांग और आपूर्ति की स्थिति में अंतर पैदा हो गया है;

और चूँकि आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने रिट याचिका 2002 की 7935 में रिट याचिका विविध याचिका 2002 की 9918 में दिनांक 26 अप्रैल, 2002 के अपने आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार को अपंजीकृत उपजकर्ताओं को फसल मौसम 2001-2002 के दौरान उनके द्वारा उत्पादित अनधिकृत एफसीवी तम्बाकू को निर्दिष्ट नीलामी मंचों पर बेचने की अनुमति देने तथा याचिका के अंतिम आदेश के लंबित रहने तक तम्बाकू बोर्ड द्वारा बिक्री प्राप्ति के 25% को रखने का निर्देश दिया था;

और चूँकि केन्द्रीय सरकार ने ऐसा करना उपयुक्त समझा था कि उपर्युक्त अंतरिम आदेश के निर्देशों के लाभ को वर्जीनिया तम्बाकू के उन अपंजीकृत किसानों को भी दिया जाए जो उक्त फसल मौसम के दौरान समस्त अपंजीकृत किसानों द्वारा उत्पादित ऐसे अनधिकृत एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के अनुमति प्राप्त याचिकाकर्ता नहीं हैं जिसकी बिक्री उनके द्वारा निर्दिष्ट नीलामी मंचों पर 4 जून, 2002 से 7 अगस्त 2002 तक की अवधि के दौरान की गई थी और ऐसे अनधिकृत एफसीवी तम्बाकू की बिक्री प्राप्ति के 25% को तम्बाकू बोर्ड द्वारा रखा गया था;

चूँकि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं जिनके कारण जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि 4 जून, 2002 से 7 अगस्त, 2002 तक की अवधि के लिए तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) के सभी या किसी प्रावधान के प्रवर्तन को स्थगित कर दिया जाए अथवा उनमें ढील दी जाए;

इसलिए अब तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 20 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा को 4 जून, 2002 से 7 अगस्त, 2002 तक की अवधि के लिए तम्बाकू बोर्ड को यह प्राधिकार देती है कि वह आंध्र प्रदेश राज्य में अपंजीकृत उपजकर्त्ताओं द्वारा उत्पादित अनधिकृत तम्बाकू की आंध्र प्रदेश में अपने नीलामी मंचों पर खरीद करने के लिए तम्बाकू बोर्ड के नियमित एवं पंजीकृत व्यापारियों तथा डीलरों को इस शर्त के तहत अनुमति प्रदान कर सकेगा कि:-

अनधिकृत तम्बाकू के लिए प्रत्येक अपंजीकृत उपजकर्त्ताओं द्वारा अतिरिक्त शुल्क के रूप में 2 रूपए प्रति किग्रा०, और सेवा प्रभार के रूप में बिक्री आय के 15% प्रतिशत का योगदान तम्बाकू निधि में किया जाएगा ।

[फा. सं. 11/1/2002-ईपी (एग्री. VI)]
अनूप के. ठाकुर, संयुक्त सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. तम्बाकू बोर्ड ने वर्जीनिया तम्बाकू के उन उपजकर्त्ताओं के पंजीकरण का नवीकरण करने से इनकार कर दिया था जिन्होंने 2000-2001 में आंध्र प्रदेश में 'फसल अवकाश' का उल्लंघन किया था । इन उपजकर्त्ताओं ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका 2002 की सं० 7935 दायर की थी । रिट याचिका 2002 की सं० 7935 में एक विविध याचिका 2002 की सं० 9918 पर आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने तम्बाकू बोर्ड के नीलामी मंचों के माध्यम से याचिकाकर्त्ताओं को उनके द्वारा उत्पादित वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री की अनुमति देते हुए एक अंतरिम आदेश दिया था बशर्ते कि बिक्री प्राप्ति के 25% को बोर्ड द्वारा एक अलग खाते में रखा जाए । यह भी आदेश दिया गया था कि बिक्री प्राप्ति रिट याचिका में अंतिम आदेशों के अधीन होगी और बिक्री प्राप्ति के शेष 75% को उपजकर्त्ताओं को वितरित कर दिया जाएगा । माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका सं० 7935 पर दिनांक 22.12.2002 के अपने निर्णय में बोर्ड को याचिकाकर्त्ताओं के पंजीकरण के नवीकरण के आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया है । बोर्ड ने इस निर्णय के विरुद्ध आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है । इस मामले में न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित है। चूंकि न्यायालय ने उपर्युक्त मामले में अपना निर्णय दे दिया है, इसलिए सरकार ने अतिरिक्त शुल्क तथा सेवा प्रभार की वसूली करने के बाद शेष राशि को वापस करने का निर्णय लिया है ।

2. इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से तम्बाकू के किसी अन्य उपजकर्त्ता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th May, 2003

S.O. 644(E).— Whereas the Central Government has been informed by the Tobacco Board that a large number of unregistered farmers have resorted to unauthorized Flue Cured Virginia tobacco (hereafter referred to as FCV tobacco) cultivation in the State of Andhra Pradesh, causing a mismatch between the demand and supply position;

And whereas the High Court of Andhra Pradesh directed the Central Government vide its order dated 26th April 2002 in W.P. M.P. 9918 of 2002 in W.P. 7935 of 2002 to permit the unregistered growers to sell unauthorized FCV tobacco grown by them during crop season 2001-2002 at designated auction platforms and to retain the 25% of the sale proceeds by Tobacco Board pending final order of the petition;

And whereas the Central Government considered it appropriate to extend the benefit of the directions of the said interim order to unregistered farmers of Virginia tobacco not being petitioners permitted the sale of unauthorized FCV tobacco produced by all unregistered farmers during the said crop season which was marketed by them during the period from 4th day of June, 2002 to 7th day of August, 2002 at designated auction platforms and 25% of the sale proceeds of such unauthorized FCV tobacco was retained by the Tobacco Board;

Whereas the Central Government is satisfied that circumstances have arisen rendering it necessary in the public interest, to suspend or relax for the period from 4th day of June 2002 to 7th day of August, 2002, the operation of all or any of the provisions of the Tobacco Board Act, 1975(4 of 1975);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 20A read with clause (g) of sub-section (2) of section 8 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government hereby authorise the Tobacco Board to admit, from the 4th day of June 2002 to 7th day of August, 2002, the regular and registered traders and dealers of the Tobacco Board to purchase, at its auction platforms in Andhra Pradesh, the unauthorized tobacco produced by unregistered farmers in the

State of Andhra Pradesh, subject to the condition that Rs 2/- per kg. as extra fee and 15% of the proceeds of the sale as service charges shall be contributed to the Tobacco Fund by every unregistered grower for the unauthorized tobacco.

[F. No. 11/1/2002-EP (Agri. VI)]

ANUP K. THAKUR, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

1. The Tobacco Board had refused renewal of registration to the growers of Virginia tobacco who had violated the 'Crop Holiday' in Andhra Pradesh in 2000-01. These growers had filed a Writ Petition No. 7935 of 2002 in the High Court of Andhra Pradesh. On a miscellaneous petition No. 9918 of 2002 in Writ Petition No. 7935 of 2002 the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh had given an interim order permitting the petitioners to sell the Virginia tobacco crop grown by them through the auction platforms of Tobacco Board subject to 25% of sale proceeds being retained by the Board in a separate account. It was also ordered that the sale proceed shall be subject to the final orders in the Writ Petition and remaining 75% of the sale proceeds shall be disbursed to the growers. The Hon'ble High Court in its judgement dated 22.12.2002 on the Writ Petition No 7935 has directed the Board to consider the applications of the petitioners for renewal of registration. The Board has filed a review petition in the High Court of Andhra Pradesh against this judgement. The decision of the Court on the same is awaited. As the Court has given its judgement in the said case the Government has decided to refund the balance amount after levying the extra fee and the service charges.

2. The giving of retrospective effect of this notification does not affect any other tobacco growers prejudicially.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2003

का.आ. 645(अ).— चूँकि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 क 4) द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जाए:

और चूँकि केन्द्रीय सरकार ने ऐसा करना उपयुक्त समझा है कि अनधिकृत फलू क्योर्ड वर्जीनिया (जिसे एतद् पश्चात एफसीवी कहा गया है) तम्बाकू की बिक्री आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू बोर्ड के निर्दिष्ट नीलामी मंचों पर की जाए;

इसलिए अब तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 4 जून, 2002 से 7 अगस्त, 2002 तक के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10 के प्रावधान के प्रवर्तन में ढील देती है और तम्बाकू बोर्ड द्वारा अधिकृत नीलामी मंचों पर अनधिकृत तम्बाकू फसल की बिक्री की अनुमति देती है।

[फा. सं. 11/1/2002-ईपी (एग्री. VI)]

अनूप के. ठाकुर, संयुक्त सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. तम्बाकू बोर्ड ने वर्जीनिया तम्बाकू के उन उपजकर्ताओं के पंजीकरण का नवीकरण करने से इनकार कर दिया था जिन्होंने 2000-2001 में आंध्र प्रदेश में "फसल अवकाश" का उल्लंघन किया था। इन उपजकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका 2002 की सं० 7935 दायर की थी। रिट याचिका 2002 की सं० 7935 में एक विविध याचिका 2002 की सं० 9918 पर आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने तम्बाकू बोर्ड के नीलामी मंचों के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा उत्पादित वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री की अनुमति देते हुए एक अंतरिम आदेश दिया था बशर्ते कि बिक्री प्राप्ति के 25% को बोर्ड द्वारा एक अलग खाते में रखा जाए। यह भी आदेश दिया गया था कि बिक्री प्राप्ति रिट याचिका में अंतिम आदेशों के अधीन होगी और बिक्री प्राप्ति के शेष 75% को उपजकर्ताओं को वितरित कर दिया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका सं० 7935 पर दिनांक 22.12.2002 के अपने निर्णय में बोर्ड को याचिकाकर्ताओं के पंजीकरण के नवीकरण के आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने इस निर्णय के विरुद्ध आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है। इस मामले में न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित है। चूँकि न्यायालय ने उपर्युक्त मामले में अपना निर्णय दे दिया है, इसलिए सरकार ने अतिरिक्त शुल्क तथा सेवा प्रभार की वसूली करने के बाद शेष राशि को वापस करने का निर्णय लिया है।

2. इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से तम्बाकू के किसी अन्य उपजकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2003

S.O. 645(E).— Whereas the Central Government is satisfied that the circumstances have arisen rendering it necessary in the public interest, that certain of the restrictions imposed by the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975) should cease to be imposed;

And, Whereas, the Central Government considered it appropriate to dispose of unauthorised Flue Cured Virginia (hereinafter referred to as FCV) tobacco at the designated auction platforms of the Tobacco Board in the State of Andhra Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 30 read with clause (g) of sub-section (2) of section 8 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government hereby relaxes the operation of the provisions of section 10 of the said Act in the State of Andhra Pradesh from the 4th day of June 2002 to 7th day of August, 2002 and permits the sale of unauthorised FCV tobacco crop at the auction platforms authorised by the Tobacco Board.

[F. No. 11/1/2002-EP (Agri. VI)]

ANUP K. THAKUR, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

1. The Tobacco Board had refused renewal of registration to the growers of Virginia tobacco who had violated the 'Crop Holiday' in Andhra Pradesh in 2000-01. These growers had filed a Writ Petition No. 7935 of 2002 in the High Court of Andhra Pradesh. On a miscellaneous petition No. 9918 of 2002 in Writ Petition No. 7935 of 2002, the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh had given an interim order permitting the petitioners to sell the Virginia tobacco crop grown by them through the auction platforms of Tobacco Board subject to 25% of sale proceeds being retained by the Board in a separate account. It was also ordered that the sale proceed shall be subject to the final orders in the Writ Petition and remaining 75% of the sale proceeds shall be disbursed to the growers. The Hon'ble High Court in its judgement dated 22.12.2002 on the Writ Petition No 7935 has directed the Board to consider the applications of the petitioners for renewal of registration. The Board has filed a review petition in the High Court of Andhra Pradesh against this judgement. The decision of the Court on the same is awaited. As the Court has given its judgement in the said case the Government has decided to refund the balance amount after levying the extra fee and the service charges.

2. The giving of retrospective effect to this notification does not affect any other tobacco growers prejudicially.